हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों का डिजिटिलीकरण

स्रोत: पी.आई.बी

भारत सरकार के **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** ने ओपन नेटवर्क डिजिटल कामर्स (ONDC) पर हिमाचल प्रदेश के ऊना एवं हमीरपुर ज़िलों की **उचित मूल्य की दुकानों (FPS)** को ऑन-बोर्ड करने के लिये एक पायलट पहल शुरू की है।

- ऐसा **पहली बार** हुआ है जब उचित मूल्य की दुकानें ONDC पर शामिल हुई हैं। इसका उद्देश्य लाभार्थियों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ-साथ FPS डीलरों को आय सृजन के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।
- **FPS** का मतलब एक ऐसी दुकान से है जिसे **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएँ वितरित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है।
  - यह शब्द राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 2(4) में परिभाषित है।
  - इसमें दैनिक खाद्य उत्पाद जैसे- चावल, तेल, चीनी, गेहूँ और अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुएँ बाज़ार मूल्य से बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
- ONDC एक स्वतंत्र रूप से सुलभ सरकार समर्थित मंच है जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद तथा बिक्री के लिये एक मंच-केंद्रित मॉडल से एक खुले नेटवर्क में स्थानांतरित करके लोकतांत्रिक बनाना है।
  - इसे 2021 में **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा लॉन्च किया गया था।

और पढ़ें: सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ONDC

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/digitalising-fair-price-shops-in-himachal-pradesh